

15.08 hrs.

SUGARCANE PRICE (FIXATION) BILL*

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): I beg to move for leave to introduce a Bill to fix the price of sugarcane.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to fix the price of sugarcane."

The motion was adopted.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I introduce the Bill.

15.8½ hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Omission of article 310, etc.)

SHRI BHAGAT RAM (Phillaur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI BHAGAT RAM: I introduce the Bill.

15.10 hrs.

UNEMPLOYMENT ALLOWANCE BILL

BY **SHRI LAKKAPPA—Contd.**

MR CHAIRMAN: We now take up further consideration of the following motion moved by Shri K. Lakkappa on the 10th March, 1978, namely:—

"That the Bill to provide for compulsory payment of allowance to all

unemployed persons in the country be taken into consideration."

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, श्री लकप्पा ने जो यह विधयक उपस्थित किया है, उस का मैं सिद्धान्त रूप में स्वागत करता हूँ लेकिन जैसा मैं ने एक रचनात्मक संशोधन उपस्थित किया है, उस के अनुसार इस में थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ।

लकप्पा साहब के अनुसार बेरोजगारी केवल शिक्षित लोगों में ही है। इस से बढ़ कर कोई बड़ा भ्रन्याय नहीं हो सकता है। जितने शिक्षित बेरोजगार हैं उन से कई गुना ज्यादा अशिक्षित बेरोजगार हैं। इसलिए उन का ध्यान उस तरह दिलाने के लिए मैं ने यह संशोधन दिया है।

श्री बसंत साठे (प्रकोला) : बिल से सब के लिए है एजूकेटेड और अनएजूकेटेड।

डा० राम जी सिंह : हमारे माननीय साठे साहब ने मूल विधयक का अध्ययन नहीं किया है। अगर ब धारा 2 को देख तो पाएंगे ;

"Every educated person including doctors, engineers..."

तो मैं यह कह रहा था कि बेरोजगारी की समस्या केवल शिक्षित लोगों की ही नहीं होती है बल्कि अशिक्षित लोगों की भी है और बेरोजगारी का सवाल केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं है बल्कि वह एक ग्लोबल फनोमेनन है और साम्यवादी देशों को छोड़ कर ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर यह सवाल न हो, यहाँ तक कि विकसित देशों जैसे अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। अगर समय रहता तो मैं आप के सामने आंकड़ देता कि किस तरह से अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित और उन्नत देशों में प्रति वर्ष बेकारी का प्रश्न बढ़ता ही जा रहा है लेकिन भारतवर्ष की

समस्या सब से ज्यादा है। भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति गिरि साहब ने "जोब कार बि मिलियन" नामक जो पुस्तक लिखी है, उस में जो बेकारी के आंकड़े दिये हैं वे करीब 13 करोड़ के हैं। यह 30 वर्षों की कमाई है हिन्दुस्तान में। प्रश्न यह है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। यह निश्चित बात है कि पार्टी के आधार पर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसमें सब लोगों को मिलजुल कर लगना होगा। वस्तुतः यह जो बेकारी का प्रश्न है, हम में हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी योजना की दिशा ही गलत थी और यही कारण है कि बेकारी दिन प्रति दिन बढ़ती गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी हुई तो केवल पौन करोड़ लोग बेकार थे, दूसरी योजना पूरी हुई तो सवा करोड़ बेकार थे, तीसरी योजना में यह सख्या पौने दो करोड़ हो गई और पंचम पंचवर्षीय योजना और 20 सूत्री और 25 सूत्री कार्यक्रम धाया, तो उसके बाद देश में 13 करोड़ आदमी बेकार हो गये हैं। इस से यह प्रमाणित होता है कि योजना की जो दिशा थी, वह निश्चित रूप से गलत थी और बेकारी पैदा करने वाली थी। इसलिए मैं यह सोचता हूँ कि बेकारी को दूर करने के लिए जो पहला प्रश्न है, वह यह है कि हमारी योजना रोजगारमुखी होनी चाहिए, एम्प्लायमेंट ऑरियन्टेड होनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि हमारी योजना रोजगारमुखी नहीं रही है लेकिन प्लानिंग से ही केवल बेरोजगारी की समस्या का दूर नहीं कर सकते हैं। अच्छा यह होगा कि हमारा "इबलपमेंट ऑरियन्टेड एम्प्लायमेंट" ही और उस रोजगार से विकास में सहायता मिले। केवल 50, 50 रुपये की भीड़ दे कर हिन्दुस्तान में भीखमगो की जमात खड़ी करने से न तो देश का विकास होगा और न रोजगार की प्रतिष्ठा होगी। इसलिए अभी भी जब हम किसी रोजगार की नीति को निर्धारित करें, तो हमें देखना होगा कि उस से राष्ट्र का विकास होता है या नहीं।

केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि दूसरी बात यह भी देखनी चाहिए कि रोजगार के सवाल को शिक्षा से जोड़ना होगा। इसलिए हमारी "एम्प्लायमेंट ऑरियन्टेड एजुकेशन" हो। पिछले 50 वर्षों से जो शिक्षा की दिशा हमें मंकाए साहब से विरासत से मिली है, उस को ही हम 30 वर्षों से ढोते रहे हैं। यही कारण है कि आज देश में इतने लोग बेकार हैं। जब तक शिक्षा में आमूल परिवर्तन नहीं होगा, जैसा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा को योजना से जोड़ा जाए यह नहीं किया जायगा, तब तक समस्या हल नहीं होगी। वर्तमान शिक्षा में केवल बेरोजगार पैदा करने की क्षमता है। जब इजीनियर और डाक्टर बेकार रहते हैं तब उनकी तरफ तो हमारा ध्यान जाता है लेकिन भारत में जो करोड़ों लोग और बेकार हैं उनकी तरफ नहीं जाता है। हिन्दुस्तान में बेरोजगारी की जो समस्या है उससे भी ज्यादा विषट, ज्यादा गम्भीर समस्या अर्ध बेकारी की है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि में लगे हुए लोगों को मान भर काम नहीं मिलता है। माल में छ या चार महीने ही काम मिलता है। देश में पांच लाख गांव हैं। सभी गांवों में अर्ध बेकारी की समस्या व्याप्त है। उनके लिए क्या हॉं सकता है। उनके लिए आवश्यक है कि कृषि का विकास किया जाए। उनके बिना गांवों में रहने वाले जो रूरल पूअर हैं उनका विकास नहीं हो सकता है। अगर इस समस्या को दूर करना है तो कृषि का विकास और उसका साथ-साथ ग्रामोद्योगों का विकास करना होगा। गांवों में रहने वालों का आप राउरवेला भिलाई, बोकारो जैसे प्लांट बना कर रोजगार नहीं दे सकते हैं। हमारी प्रपनी सीमाय है। हमारे पास ज्यादा पूजी नहीं है। बड कारखानों में जहाँ एक आदमी को रोजगार देने में पांच लाख रुपये लगता है वहाँ छोटा रोजगार देने में लघु उद्योग स्थापित करने में और उस में उनको रोजगार देने में केवल पांच रुपये की पूजी लगती है। इसीलिए

[श्री रामजी सिंह]

इंग्लैंड के बड़े अर्थशास्त्री थ्यूमाबर ने कहा है कि "स्माल इज ब्यूटीफुल"। हिन्दुस्तान जैसे विकासशील देश में बड़े उद्योगों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो बड़े उद्योग आवश्यक हैं वे तो लगने चाहिये। लेकिन जहाँ उनकी आवश्यकता नहीं है, नहीं लगने चाहिये। अगर बेरोजगारी को देश में दूर करना है तो निश्चित रूप से कुछ का विकास करना होगा और उसके साथ साथ ग्रामीणों का विकास करना होगा।

इस समस्या का हल सुझाने के लिए भगवती कमेटी ने काफी सुझाव दिए हैं। मैं उन की पुनरावृत्ति करके इस महान सदन का समय अपव्यय नहीं करना चाहता। लेकिन इसके मिलसिले में जो प्रस्ताव लक्ष्मी साहब से एक बड़े सुन्दर हृदय से लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए रखा है कि एलाउंस दिया जाए उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि यह ठीक बात है कि कुछ राज्यों ने एलाउंस दिया है, भारत में सब से ज्यादा गणित बेरोजगार बंगाल में है और वहाँ की सरकार ने एलाउंस उनको दिया है, इसका मैं विरोध नहीं करता हूँ लेकिन प्रश्न यह है कि केवल कुछ लोगों को दस बीस या पचास रुपये दे देने से समस्या हल हो जाएगी? जब योजना प्रायोग के सामने यह समस्या आएगी तो उसको सोचना होगा कि इसको कैसे हल करना चाहिए। सचमुच में जनता पार्टी के घोषणापत्र में हम लोगों ने वायदा किया है कि सभी को हम रोजगार दग। लेकिन क्या एक वर्ष में रोजगार दिया जा सकता है? सचमुच में इसके लिए दस वर्ष का कार्यक्रम घोषित किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यह कार्यक्रम और यह बाणी खोजली साबित हुई तो जनता पार्टी का भी वही हाल होगा जो हमारे विरोधी मिलों का हुआ है। इसलिए आवश्यक है कि दस वर्ष की इस योजना को साकार किया जाए इसको मूर्त रूप दिया

जाए और हम सब लोगों को सरकार से माह्रद करना चाहिये कि कालवृद्ध कार्यक्रम के अनुसार, एक वर्ष में कितने दो वर्ष में कितने लोगों को रोजगार, काम देना चाहिये और इस तरह से इस समस्या को हल करने के लिए हमें प्रागे बढ़ना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि "राइट टू वर्क" अधी संविधान में शामिल कर दिया जाए। मैंने विधेयक भी उपस्थित किया है इसके सम्बन्ध में अगर आप संविधान में संशोधन कर देते हैं कि हर प्रादमी को रोजगार दिया जाए और यह उसका अधिकार है तो भारत का योजना प्रायोग जो है उससे अगर आप जा कर पूछें कि वह क्या एका एक ऐसा कर मकेगा तो इसी नतीजे पर पहुँचे कि आज वह विफल और असफल होगा। इसलिए "राइट टू वर्क" सिद्धान्त ठीक है लेकिन उसको दस वर्ष में बांध देना चाहिये।

लक्ष्मी साहब ने कहा है कि जितने बेरोजगार हैं उनको एलाउंस दिया जाए। कितनों को देंगे? हिन्दुस्तान में बेकारों की संख्या चार, पांच हजार या साठ में तो है नहीं, 30 सालों के शासन के कारण प्राय 13 करोड़ लोग बेकार हैं। वह कहते हैं कि 15 करोड़ २० लखेना। तो माननीय लक्ष्मी के गणित और अंकगणित की परिभाषा दूसरी होगी, मेरे विचार से इसके लिये 40 अरब रुपये लगेंगे, जो हिन्दुस्तान की प्राथिक योजना की शक्ति के बाहर की बात है। इसलिये ऐसी बात करनी चाहिये जो अच्छी हो और व्यावहारिक हो। और जैसे जैसे देने से क्या होगा कि मिळमंजी की प्रवृत्ति बढेगी। इसलिये मैं माननीय लक्ष्मी की भावना का भावर करता हूँ और अपनी सरकार से, कृष्णसीढी है कि अम मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि यह सचमुच में ऐसा रोजगार दें जिससे अम की प्रतिष्ठा बढे। प्रोब्लेम से रुपया लेने वाले का तो अपमान है ही, देने वाले का भी अपमान है ॥

इसलिये आप लोगों को भीख स्वरूप न दीजिये, बल्कि काम दीजिये और देते जाइये न कि कई तभी जनता पार्टी और राष्ट्र का सम्मान बढ़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय लक्ष्मणा की भावना का धारण करते हुए उनसे अनुरोध करना कि मेरा जो निर्दोष संशोधन है उसको स्वीकार कर लें। और जैसा मैंने कहा है :

"The Government, keeping in view the financial resources, will execute the Unemployment Allowance Scheme in phase starting with the Scheduled Caste and Scheduled Tribes and Backward Classes."

जो समाज का सबसे अन्तिम व्यक्ति हैं वही से करना चाहिये। इसीलिये जो भी हम काम करें, चाहे काम देने का हो, तो समाज का जो अन्तिम व्यक्ति है वही से हम अपना कार्य करना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द कछवाय (उज्जैन) : सभापति महोदय, मुझे एक विधेयक पेश करना था।

सभापति महोदय : घण्टी बात है, इनको इंट्रोड्यूस कर लेने दीजिये बिल।

श्री नाबू सिंह (दीसा) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्राइवेट मेम्बरस बिल पर साढ़े तीन बजे बहुत होनी थी, पहले मेरा नाम था और मैं बैठा रहा, और आपने हमारा नाम समय से पहले बुला दिया।

सभापति महोदय : आपकी व्यवस्था का प्रश्न मैंने सुन लिया। सदन से हमने पूछा था, प्राक्रियल बिजनेस समाप्त हो गया था। तो या तो सदन 24 मिनट के लिये ऐडजर्न कर के फिर दुबारा मिलते, या सदन का काम चालू रहते समय ऐडवांस कर के प्राइवेट मेम्बरस बिजनेस का। हाउस ने एक

मत से निर्णय दिया कि प्राइवेट मेम्बरस बिजनेस को ऐडवांस कर दिया जाय। हमने कर दिया। आप बाद में धाये। आपकी भी बुला लिया जाया, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको तकलीफ न हो उसके लिये व्यवस्था की है। जो अपने बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सके उनको बीच में इंटरप्ट कर इजाजत दी जा रही है। कोई परेशानी की बात नहीं है।

15.22 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL

(Amendment of Articles 330 and 332)

श्री कृष्ण चन्द कछवाय (उज्जैन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न है :

श्री कृष्ण चन्द कछवाय : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

The motion was adopted.

श्री कृष्ण चन्द कछवाय : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित भी करता हूँ।

15.23 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL

(Amendment of Seventh Schedule)

श्री कृष्ण चन्द कछवाय (उज्जैन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।